

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक- 05/11/2008

विषय:- मसूरी, जनपद देहरादून में सिविल न्यायालय की स्थापना हेतु भूमि हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-644/आ0ले0-2008 दिनांक- 28-09-2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मसूरी जनपद देहरादून में गांधी शताब्दी नैत शिक्षितालय मसूरी द्वारा हरतगत कुल 10,000 (दस हजार) वर्ग फीट भूमि सिविल न्यायालय की स्थापना हेतु वित्त अनुभाग-3 के शारानादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15-02-02 के प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन न्याय विभाग उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
- 3- हस्तान्तरित भूमि-यदि प्रस्तावित कार्य से गिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही गिहित हो

जायेगी।

- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की गयी है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, संगिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
 - 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की गयी है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
 - 7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुगम्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
- कृपया तदनुरार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

पृ०५० संख्या-११०३(१) / रागदिनांकित / २००८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- महानियन्धक, मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
- 3- निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय।
- 4- प्रभाषी गीडिया केन्द्र सचिवालय।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा रो,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।